सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(बी.ए.डी.पी.)

परिचय

देश की करीब 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 14 विकास खण्डों शिव, बाडमेर, चौहटन, धोरीमन्ना, जैसलमेर, सम, बीकानेर, कोलायत, खाजूवाला, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, रायसिंहनगर व अनूपगढ में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मोडीफाईड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया । इस कार्यक्रम के लिये शत–प्रतिशत सहायता राशि भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती हैं । गृह मंत्रालय (बी.एम.) भारत सरकार द्वारा नए निर्देश जारी किये गये है जो फरवरी 2014 से प्रभावी हैं ।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं ।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हैं ।
- भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, विकास खण्ड की जनसंख्या एवं विकास खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि में से 30–30 प्रतिशत राशि बाडमेर एवं जैसलमेर जिलो को 25 प्रतिशत राशि बीकानेर जिलें एवं 15 प्रतिशत राशि गंगानगर जिले को आवंटित की जाती है।

विशेषाताएं

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेष इकाई होता हैं एवं समस्त कार्य विकास खण्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किये जाते हैं ।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्क्रीनिग कमेटी द्वारा किया जाता हैं ।
- योजना में सामाजिक सैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबंधित कार्यो पर बल दिया जाता हैं ।
- सुरक्षा संबंधी कार्य भी कराये जा सकते हैं लेकिन आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत इस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता हैं ।
- पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सडक एवं पुलिया इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना के कार्यो पर 60 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती है ।

- वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती हैं । कार्यो का सम्पादन राज्य/केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थाये/पंचायती राज संस्थाएं/ जिला कोन्सिल/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता हैं ।

उपलब्धियां

- वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर 2014 तक रु. 9955.51 लाख रूपये व्यय कर 979 कार्य पूर्ण कराये गये है ।